जामिया मिलिया इस्लामिया
नई दिल्ली-110025

13 जुलाई 2021

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया में "भूटान'स फॉरेन पॉलिसी: कोपिंग विद जिओ-पोलिटिकल डाईलेमास" पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन

एमएमएजे अंतर्राष्ट्रीय अध्धयन अकादमी ने 12 जुलाई 2021 को "भूटान'स फॉरेन पालिसी: कोपिंग विद जिओ-पोलिटिकल डाईलेमास" पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया। प्रोफेसर राजेश खरत, निदेशक, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, मुंबई विश्वविद्यालय ने व्याख्यान दिया। .

प्रो. अजय दर्शन बेहरा, कार्यवाहक निदेशक, एमएमएजे-एआईएस ने वक्ता और प्रतिभागियों का स्वागत किया। अपने उद्घाटन भाषण में, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भूटान, जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (जीएनएच) की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था, पिछले कई वर्षों से कुछ भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। भूटान, एक छोटा देश अपने दो बड़े पड़ोसियों, भारत और चीन के बीच भू-राजनीतिक युद्धाभ्यास में फंस गया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भूटान कैसे इन चुनौतियों का सामना कर रहा है।

प्रो. खरत ने भूटान की विदेश नीति की प्रकृति का वर्णन करते हुए शुरुआत की और तर्क दिया कि यह भू-रणनीतिक के बजाय भू-राजनीतिक है। उन्होंने भूटान की विदेश नीति पर चीन और भारत के जबरदस्त प्रभाव पर प्रकाश डाला और बताया कि यह भूटान की विदेश नीति के विकल्पों को सीमित करता है। भूटान की विदेश नीति के विमर्श में यह पहलू बहुत स्पष्ट है। भूटान के राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच अपने दो बड़े पड़ोसियों के साथ भूटान के संबंधों के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण देखे जा सकते हैं। लेकिन समय के साथ, भूटान की विदेश नीति अधिक परिपक्व हो गई है।

प्रो. खरत ने भूटान की विदेश नीति के विभिन्न ऐतिहासिक वक्रों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने 1949 में भूटान और भारत के बीच हस्ताक्षरित "सतत शांति और मित्रता संधि" के बारे में विस्तार से चर्चा की। उनकी राय में इस संधि ने भूटान और भारत के बीच सदैव संबंधों को समेकित किया। 1949 की संधि की भावना को बरकरार रखते हुए, भारत और भूटान ने 2007 में एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि भूटान की संप्रभुता बरकरार रहेगी और दोनों देश एक-दूसरे की हर संभव मदद करेंगे। 1959 में तिब्बत पर चीनी कब्जे ने भूटान और तिब्बत के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को ठेस पहुंचाई। इस विकास ने भूटान में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी जिसने भूटान देश को राज्य द्वारा प्रचलित अलगाववाद की सदियों पुरानी नीति को त्यागने के लिए प्रेरित किया। भूटान ने मानवीय आधार पर तिब्बती शरणार्थियों के लिए अपना क्षेत्र खोलने का भी फैसला किया, जिसे चीनियों ने उदारता से नहीं देखा।

प्रो. खरत ने भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद और भूटान पर चीन द्वारा लागू की गई दबाव रणनीति के बारे में भी बात की। 2017 में डोकलाम घाटी में चीन द्वारा किए गए क्षेत्रीय दावों ने भूटान पर नए दबाव बनाए। इस मुद्दे ने भारत-भूटान-चीन त्रिकोण के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक आयामों का संकेत दिया। भूटान ने चीन से संभावित क्षेत्रीय खतरों को पहचान लिया और वह भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हुए इसका मुकाबला करने के लिए एक रणनीति विकसित करने की कोशिश कर रहा है। प्रो. खरत ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में चीन भूटान से निपटने में नरम कूटनीति पर अधिक भरोसा करता रहा है लेकिन समकालीन काल में यह बदल रहा है।

व्याख्यान में देश भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। व्याख्यान के बाद एक विस्तृत प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया जिसमें संकाय सदस्यों और प्रतिभागियों द्वारा कई प्रश्न उठाए गए। प्रो. अजय दर्शन बेहरा, कार्यवाहक निदेशक, एमएमएजे-एआईएस ने स्पीकर को उनके व्यावहारिक विश्लेषण और प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया